sentative on the Senate, was received by the Kerala Education Department.

(b) Representation is given to Municipalities and Trivandrum Corporation but not to Calicut Corporation because the latter was not in existence when the Kerala University Act was passed.

(c) The question of bringing in substantial changes in the Kerala University Act is under consideration. The request of the Calicut Corporation for representation on the Senate will be considered when the Draft Bill to amend the Kerala University Act is finalised.

Release of D.I.R. Prisoners on Parole

220. Shri Mohammed Koya: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of prisoners detained under the Defence of India Rules who were released on parole till 1st August, 1965;

(b) if so, the reasons for their release; and

(c) the number of persons refused permission and the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना

221. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य में अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया है ;

(ख) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है जो अब तक कलकत्ता वापस आ गये हैं ; और

(ग) उसके क्या कारण है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) 10 जुलाई, 1965 तक 9,864 परिवार दण्डकारण्य में बसाये गये हैं ।

(ख) 844 परिवार अपने ग्राम स्थानों को छोड़कर चले गये हैं । इन परिवारों में से, यदि कोई कलकत्ता वापस चले गये हों और कितने गये है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) जो परिवार कलकत्ता वापस चले गये होंगे उनसे संपर्क के अभाव में उनके वापस लौटने के कारण बताना संभव नहीं है । इस बारे में श्रीमती रेणुका बड़कटकी के तारांकित प्रश्न संख्या 1070, दिनांक 28-4-65 के उत्तर के सम्बन्ध में जो विवरण सभा की मेज पर रखा गया था, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा गांवों को छोड़कर जाने वाले कुछ परिवारों के कारणों का सामान्य मूल्यांकन किया गया है ।

काश्मीर के सिनमा-घरों में राष्ट्रगान

222. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में सिनेमा समाप्त होने पर राष्ट्रगान की धुन नहीं बजाई जाती ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें

223. **श्री ह्रा० ना० तिवारी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है कि उम्मीदवारों को गहन ज्ञान न होने के आधार पर उनके अंक घटाने का संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार समाप्त कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) सरकार का विचार है कि भरती के स्तर को ऊंचा बनाये रखने के लिये गहन ज्ञान न होने के आधार पर अंक घटाने की व्यवस्था बनी रहनी चाहिये ।

Supply and Distribution of Petroleum Products

224. **Shri Yashpal Singh:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Sezhiyan:
Shri Kajrolkar:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the effect of the promulgation of Rules under the Defence of India Act, 1962 to ensure unhindered supply and distribution of petroleum products;

(b) whether any prosecutions have been made under the Rules; and

(c) whether any private petrol pumps have been taken over by Government?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) The Government of India have assumed enabling powers under the Defence of India Rules by means of the following orders:

(i) Petroleum Products (Collection of Information) Order, 1965.

(ii) Petroleum Products (Supply and Distribution) Order, 1965.

Under the first order, the Oil Companies can be compelled to furnish information to the Central Government, the State Governments, and the Collectors concerned regarding the stocks held and in transit on every Monday at every installation and depot, information about supplies made on shore and by coastal movement, refinery production actually achieved during the preceding month and expected during the following month etc. Under the second order Government can order the Oil Companies to arrange coastal and inland movements ex-refineries to ensure equitable distribution of petroleum products. This order also gives powers to State Governments and Collectors, within their respective jurisdiction, to issue directions to the dealers/agents and officers incharge of depots (with Central Government's prior approval) for equitable distribution of stocks. The powers for inspection and search of stocks have also been vested. It has not been considered necessary to enforce these Orders as yet because the Oil Companies are furnishing regularly information about stocks held, stocks in transit etc. and are co-operating with the Government in the implementation of movement plans.

(b) and (c). No, Sir.

Construction of Houses in Delhi

225. **Shri Gokulananda Mohanty**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Central Government had instructed the Delhi Administration that it should not enforce its order fixing a time-limit for